

21-11-22

वकील उमयपक्ष उप- है। अपाधी सं- 1 से जवाब प्रस्तुत करना नहीं चाहे है। कल अपाधी सं- 1 का जवाब कंड किया जाता है। वास्तै वदस पत्रा- दि 16-11-22 को पेश हो

16-11-22

वकील उमयपक्ष उप- है। वास्तै वदस पत्रा- दि 23-11-22 को पेश हो

23-11-22

पत्रावली पेश हुई/वकील वादी/प्रतिवादी/ अपीलार्थी/रेस्पॉन्डेंट/प्रार्थी/अप्रार्थी/उमयपक्ष उपस्थित है/अनुपस्थित है। श्रीमान् पीठासीन अधिकारी उमय पर है/अवकाश पर है/अन्य C.M. विजिट कार्यों में व्यस्त है/का स्थानांतरण हो गया है।
धतः पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक... 28-11-22 को पेश हो।
W.P.C.
रीडर

28-11-22

वकील उमयपक्ष उप- है। वास्तै वदस पत्रा- दि 12-12-22 को पेश हो

12-12-22

वकील उमयपक्ष उप- कदस सुनी गई। वास्तै निर्णय पत्रावली दि 23-12-22 को पेश हो

23-12-22

वकील उमयपक्ष उप-। समयाभाव के कारण निर्णय नहीं किया जा सका। वास्तै निर्णय पत्रावली दि 28-12-22 को पेश हो

26/12/22

उप जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी (संमा०)
वकील उमयपक्ष उप- प्रार्थी/अप्रार्थी/उमयपक्ष द्वारा प्रस्तुत महाभारत सं- का 09K13PC आधारहीन को कारण खारिज किया जाता है। निर्णय पत्रावली दि 26/12/22 को पेश हो।
पत्रावली दिनांक पत्रावली फेसल शुमार टोकल नम्बर से इन से एवं का तदमील साक्षात्पता है।

उप जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी (संमा०)

निर्णय न्यायालय श्री नरेन्द्र कुमार मीना, आर०ए०एस०, उप जिला
कलेक्टर एवं उप जिला मजिस्ट्रेट गंगपुर सिटी जिला सवाई माधोपुर
मुकदमा नम्बर तारीख रजू तारीख निर्णय

36/2022

5.7.2022

26.12.2022

1. कुरू उर्फ राजेश पुत्र जगमोहन, मीना निवासी बनेगा तह० गंगपुर सिटी
2. गणेश पुत्र रामजीलाल, मीना निवासी बनेगा तह० गंगपुर सिटी
3. दयासलो पत्नी जगमोहन, मीना निवासी बनेगा तह० गंगपुर सिटी
4. धर्मी पुत्र जगमोहन, मीना निवासी बनेगा तह० गंगपुर सिटी
5. सीमा पुत्री जगमोहन, मीना निवासी बनेगा तह० गंगपुर सिटी

—प्रार्थीगण/प्रतिवादीगण

बनाम

1. बृजमोहन पुत्र रामजीलाल, मीना निवासी बनेगा तह० गंगपुर सिटी
2. शाखा प्रबन्धक, पंजाब नेशनल बैंक शाखा गंगपुर सिटी
3. लैण्ड होल्डर तहसीलदार गंगपुर सिटी —अप्रार्थी/वादी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 9 नियम 13 सी०पी०सी० व 151 सी.पी.सी.

उपस्थित :- श्री हरिशंकर शर्मा, एडवोकेट, प्रार्थीगण की ओर से

श्री मोहम्मद इस्लाम, एडवोकेट, अप्रार्थी नं० 1 की ओर से

निर्णय

उपरोक्त उनवानी वाजदायरी प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 9 नियम 13 सी०पी०सी० प्रार्थीगण कुरू उर्फ राजेश वगैरा की ओर से इस आशय का प्रस्तुत किया गया है कि अप्रार्थी/वादी बृजमोहन ने प्रार्थीगण/प्रतिवादीगण के विरुद्ध एक दावा उनवानी बृजमोहन बनाम कुरू वगै वाबत विभाजन एवं स्थायी निषेधाज्ञा पेश किया था। जिसमे प्रार्थीगण एवं अप्रार्थी की अराजी ख. नं. 763 रकवा 0.23 हैक्टर, खं० नं. 729 रकवा 0.46 हेक्टर, खं. नं. 741 रकवा 0.11 हेक्टर, खं० नं. 910 रकवा 0.21 हेक्टर, खं० नं. 729/963 रकवा 0.01 हैक्टर गै.मु.चा. कुल किता 5 कुल रकवा 1.02 हैक्टर स्थित ग्राम बनेगा में प्रार्थीगण एवं अप्रार्थी मौखिक बटवारे अनुसार कब्जा काश्त करते चले आ रहे है एवं ख. नं. 763 रकवा 0.23 हेक्टर बंजड पड़ा हुआ है जिसमें दरख्त पेड़ उग रहे है उक्त नम्बर पर प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण के मध्य विवाद की बजह से मौखिक बटवारा नहीं कर रखा है और बंजड छोड़ रखा है शेष रकवा पर प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण ने मौके पर 1/3 - 1/3 मौखिक बटवारा कर रखा है। माननीय न्यायालय ने निर्णय व डिक्री के मुताबिक बिना प्रार्थीगण/प्रतिवादीगण को सुने राजस्व रिकॉर्ड में विभाजन स्कीम के मुताबिक अप्रार्थी/वादी के नाम खातेदार लगाये जाने के नाम विधिविरुद्ध होने से डिक्री व निर्णय निरस्त होने योग्य है। माननीय न्यायालय की आदेशिका दिनांक 27-9-2021 में प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 सीपीसी की बहस सुनी गई और निर्णय दिनांक

कुरु वगैरा बनाम बृजमोहन वगैरा, प्रा0पत्र वाजदायरी

(2)

15/2/2022 के पेज नं. 3 में तीन लाईन छोड़कर चौथी लाइन पर दिनांक 27/9/2021 को वादी व प्रतिवादी के मध्य वादग्रस्त भूमि का विभाजन स्कीम बनवाने का निवेदन किया। दोनो तथ्य उक्त दिनांक से मेल नहीं खाते हैं ऐसी सूरत में निर्णय व डिक्री निरस्त होने योग्य है। दिनांक 27/6/2022 को प्रार्थीगण अपने हिस्से मुताबिक भूमि बरसात होने के बाद जोत लगाने व बीज बोने के लिए गये तो अप्रार्थी ने जोत लगाने से मना कर दिया कि अब तुम्हारा उक्त भूमि से कोई सम्बन्ध नहीं है। मैंने न्यायालय से दावा डिक्री करवा लिया है तब प्रार्थीगण उसी दिवस को अपने अधिवक्ता से आकर मिले तो अधिवक्ता ने बताया कि आप तारीखों पर नहीं आये इसलिए मैंने आपका दावा आपके बिना सूचना दिये ही पैरवी करने से छोड़ दिया तब प्रार्थीगण ने स्वयं ही अदालत में जाकर उक्त प्रकरण की जानकारी करके दिनांक 27/6/2022 को नकल प्रार्थना पत्र पेश किया। जिनकी नकल प्रार्थीगण को दिनांक 28/6/2022 को नकल मिलने से सम्पूर्ण प्रकरण की जानकारी हुई। दिनांक 28/6/2022 को नकल निर्णय, डिक्री व सम्पूर्ण आदेशिका का अवलोकन करने पर दिनांक 17/12/2021 को अप्रार्थी अधिवक्ता ने पैरवी को हिदायत नहीं होना बताया वकील वादी को सुना गया दावावादी प्राथमिक डिक्री किया जाता है विस्तृत निर्णय पृथक से लिखा जाकर पत्रावली में शामिल किया गया विभाजन स्कीम तलब की जाकर पत्रावली दिनांक 10/1/2022 को पेश है जबकि उक्त दिवस को माननीय न्यायालय में अप्रार्थी अधिवक्ता को पैरवी हिदायत नहीं होने की सूचना पर न्यायालय को पुनः प्रार्थीगण को सूचित किया जाना न्यायहित में आवश्यक है इसी बिना पर निर्णय व डिक्री निरस्त होने योग्य है। माननीय न्यायालय द्वारा विभाजन स्कीम तैयार करने हेतु हल्का पटवारी को जारी किये गये आदेश के मुताबिक दिनांक 13/1/2022 को अप्रार्थी हल्का पटवारी से मिली भगत करके बिना प्रार्थीगण को सूचना दिये ही घर बैठकर मनमाने तरीके से विभाजन स्कीम पर मात्र हल्का पटवारी एवं अप्रार्थी बृजमोहन के हस्ताक्षर हैं जिससे साफ जाहिर होता है कि हल्का पटवारी द्वारा पेश की गयी विभाजन स्कीम प्रार्थीगण/प्रतिवादी की अनुपस्थिति में बनाई गयी है उक्त रिपोर्ट के मुताबिक प्रार्थीगण व अप्रार्थी का उक्त विभाजन स्कीम के अनुसार कोई कब्जा काश्त नहीं है और न ही विभाजन स्कीम पर स्वतंत्र गवाहों के हस्ताक्षर हैं जिससे यह जाहिर होता है कि हल्का पटवारी ने मौके पर जाकर खेतों की नाप तोल नहीं की है मात्र अप्रार्थी/वादी के कहे अनुसार ही हल्का पटवारी ने विभाजन स्कीम तैयार कर पेश की है जबकि मौके पर ख. नं. 763 रकवा 0.23 हैक्टर बंजड़ पड़ा हुआ है जिसमें दरख्त पेड़ खड़े हुए हैं शेष रकवा व गै.मु.चा.में प्रार्थीगण व अप्रार्थी का 1/3

कलेक्टर
(स०मा०)

हिस्सा मौखिक बटवारा अनुसार उपयोग-उपभोग काश्ते करते चले आ रहे है। इसी बिना पर निर्णय व डिक्री निरस्त होने योग्य है अप्रार्थी ने महत्वपूर्ण तथ्यों को छुपाते हुए माननीय न्यायालय को गुमराह करते हुए एवं हल्का पटवारी से मिलीभगत करके आनन फानन मे उक्त निर्णय के मुताबिक राजस्व रिकॉर्ड में विभाजन स्कीम के मुताबिक बटवारा कर अलग से खाता कायम करवा लिया इस कारण से निर्णय व डिक्री निरस्त किये जाने योग्य है। प्रकरण राजस्व अचल सम्पत्ति से सम्बन्धित है तथा उक्त भूमि प्रार्थीगण का जीविकोपार्जन का एक मात्र साधन है। इसलिए उक्त भूमि में प्रार्थीगण के हित निहित है एकपक्षीय निर्णय व डिक्री पारित होने के कारण प्रार्थीगण के महत्वपूर्ण अधिकार व सांपत्तिक हित प्रभावित होंगे। प्रकरण में दोनो पक्षो को विधि अनुसार सुना जाकर गुणवत्ता के आधार पर प्रकरण का निस्तारण किया जाना आवश्यक है। प्रार्थीगण दिनांक 26/6/2022 को जब अपने खेतो पर गये तो प्रार्थीगण को देखकर अपने साथ कुछ लोगो को लेकर प्रार्थीगण के खेतो पर आ गये तथा प्रार्थीगण को वहां से चले जाने के लिए कहा, कारण पूछने पर अप्रार्थी द्वारा बताया किया उक्त खेतो के सम्बन्ध में मैने एस.डी.एम. कोर्ट गंगापुर सिटी से दावा पेश करके डिक्री ले ली है अब तुम खेतो पर न तो आओगे और न ही काश्त करोगे जिस पर प्रार्थीगण ने दिनांक 27/6/2022 के न्यायालय मे जाकर प्रकरण के बारे जानकारी प्राप्त की, निर्णय व डिक्री की नकल प्राप्त की तब जाकर अप्रार्थी द्वारा सम्पूर्ण फर्जी कार्यवाही के बारे मे जानकारी प्राप्त हुई। इस आधार पर यह प्रार्थना पत्र अन्दर मियाद बिना किसी बिलम्ब के उचित न्याय शुल्क के साथ प्राप्त किया जा रहा है फिर भी सतर्कवश धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत है इस कारण प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने मे हुई देरी को न्यायहित मे कन्डोन फरमाया जावे। अतः प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार जाकर माननीय न्यायालय द्वारा निर्णय व डिक्री दिनांक 15/2/2022 मुकदमा संख्या 73/2019 उनवानी बृजमोहन बनाम कुरु उर्फ राजेश वगै0 में पारित एकपक्षीय निर्णय व डिक्री को अपास्त फरमाया जावे व प्रार्थीगण को प्रकरण मे सुनवाई का उचित अवसर देते हुये गुणवत्ता के आधार पर प्रकरण का विधिवत् निर्णय करने के आदेश फरमाये जावे।

प्रार्थना पत्र के साथ प्रार्थीगण ने धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथपत्र, नकल निर्णय व डिक्री दिनांक 15.2.2022 प्रस्तुत किये है।

कुरु वगैरा बनाम बृजमोहन वगैरा, प्रा0पत्र वाजदायरी

(4)

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 2 व 3 बाबजूद सूचना उपस्थित नहीं हुए अतः अप्रार्थी संख्या 2 व 3 के विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही की गई।

अप्रार्थी संख्या 1 की ओर से बाजदायरी प्रार्थना पत्र का कोई जबाब प्रस्तुत नहीं किया गया।

प्रार्थना पत्र पर बहस विद्वान वकील उभयपक्ष सुनी गई।

प्रार्थीगण के विद्वान वकील ने अपने बाजदायरी प्रार्थना पत्र के अनुरूप बहस करते हुए प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार करने का निवेदन किया है।

वकील प्रार्थीगण ने अपने बाजदायरी प्रार्थना पत्र के अनुरूप लिखित बहस भी प्रस्तुत की है। जो पत्रावली में संलग्न है।

अप्रार्थी संख्या 1 के विद्वान वकील ने अपनी बहस में कहा कि प्रतिवादीगण मूल वाद में नियमित रूप से पैरवी करते रहे हैं एवं जबाब के साथ इन्होंने अपना काउन्टर क्लेम भी प्रस्तुत किया है। जिस पर न्यायालय द्वारा विधिवत रूप से तनकी कायम की गई एवं प्रकरण में साक्ष्य ली गई। प्रार्थीगण/प्रतिवादीगण ने दिनांक 11.11.2021 को प्रतिवादी राजेश के बयान भी दर्ज कराये हैं तथा इसके पश्चात साक्ष्य हेतु कई अवसर लिये हैं। दिनांक 17.12.2021 को प्रार्थीगण/ प्रतिवादीगण के वकील द्वारा प्रकरण में पैरवी नहीं की गई। फलस्वरूप दावा प्राथमिक डिक्री किया जाकर विभाजन स्कीम मंगवाई गई। विभाजन स्कीम के समय भी प्रतिवादीगण मौके पर उपस्थित थे परन्तु इन्होंने विभाजन स्कीम पर हस्ताक्षर करने से मना कर दिया। जिसका नोट विभाजन स्कीम पर भी अंकित है। दावा विधिवत रूप से डिक्री किया गया है एवं भूमि का विभाजन किया गया है। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आधारहीन है जो खारिज फरमाया जावें।

बहस पर मनन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया। साथ ही मूल वाद की पत्रावली का भी अवलोकन किया गया। प्रार्थीगण/ प्रतिवादीगण ने अपने प्रार्थना पत्र में मुख्य रूप से यह आपत्ति ली है कि विभाजन स्कीम प्रार्थीगण/प्रतिवादीगण की अनुपस्थिति में बनायी गई है। भूमि पर अप्रार्थी का कब्जा नहीं है एवं विभाजन स्कीम पर स्वतंत्र गवाहों के हस्ताक्षर नहीं हैं। खसरा नम्बर 763 पडत पडा हुआ है। विभाजन स्कीम के अवलोकन से स्पष्ट है कि पटवारी हल्का एवं नायब तहसीलदार गंगापुर सिटी द्वारा विभाजन स्कीम प्रार्थीगण/प्रतिवादीगण एवं अप्रार्थी बृजमोहन की उपस्थिति में बनाई गई है। जिस पर प्रार्थी/प्रतिवादी गणेश, धर्मी, राजेश ने हस्ताक्षर करने से मना किया गया। इसका नोट पटवारी हल्का व नायब तहसीलदार गंगापुर सिटी द्वारा अपने विभाजन स्कीम में अंकित

कुरु वगैरा बनाम बृजमोहन वगैरा, प्रा०पत्र वाजदायरी

(5)

किया हुआ है। जहाँ तक ख०न० 763 का प्रश्न है प्रार्थीगण/प्रतिवादीगण इस नम्बर को बंजड व पडत बताते है परन्तु विभाजन मे यह नम्बर अप्रार्थी बृजमोहन को दिया गया है। बंजड/पडत भूमि ख०न० 763 अप्रार्थी को देने पर आपत्ति तो अप्रार्थी को होनी चाहिए थी परन्तु अप्रार्थी बृजमोहन ने कोई आपत्ति प्रस्तुत ही नहीं की है एवं विभाजन स्कीम के अनुसार भूमि का विभाजन स्वीकार किया है। प्रार्थीगण/प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत आपत्तियाँ आधारहीन है। फलस्वरूप प्रार्थीगण/प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश 9 नियम 13 सी.पी.सी. अस्वीकार किये जाने योग्य है।

आदेश

अतः उपरोक्त विवेचन के अनुसार प्रार्थीगण/प्रतिवादीगण कुरु उर्फ राजेश वगैरा द्वारा प्रस्तुत यह वाजदायरी प्रार्थना पत्र आदेश 9 नियम 13 सी.पी.सी. आधारहीन होने के कारण अस्वीकार किया जाकर खारिज किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 26.12.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया ।



(नरेन्द्र कुमार मीना)
उप जिलाकलेक्टर
गंगापूर सिटी
उप जिला कलेक्टर
गंगापूर सिटी (स०मा०)